बिहार-विधान-सभा-वादवृत्त

बृहस्पतिवार तिथि ५ जून १९५२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्यविवरण

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ५ जून १९५२ को पूर्वाह्न १० बजे माननीय अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा, के सभापतित्व में हुआ।

सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक पर साधारण वाद-विवाद

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET FOR THE YEAR 1952-53.

माननीय अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री के उत्तर के बाद, आज प्रश्नोत्तर का समय आरम्भ होगा।

माननीय डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कितने दिनों तक बजट के ऊपर बहस होने के पश्चात मुझे कुछ बयान करने का मौका मिला है। बजट जितने दृष्टिकोण से देखा गया है और उसके सभी अंगों की जो आलोचना और प्रत्यालोचना हो रही है, उसको जहांतक मैं समय बचा सका, सुनने की कोशिश की है। सबसे पिछली तकरीर जो हमारे डिप्टी लीडर सोशलिस्ट पार्टी ने की है, उसके विषय में मैं सोचता हूं कि क्या कहूं। उन्होंने एक लम्बा, गवेषणापूर्ण, विद्वत्तापूर्ण भाषण दे दिया। बजट के साथ उसका क्या संबंध है इसको विचारना है। मेरा ख्याल है कि बजट से उसका कोई खास संबंध नहीं है। हो सकता है कि पार्लियामेंट में इस स्पीच की जरूरत हो। और वह स्पीच मीजू समझी जाय। हो सकता है कि किसी पब्लिक मिटिंग में सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श को जताने के लिये स्पीच दी जाय तभी यह रिलेभेंट कही जा सकती है। इस भवन में एक छोटे बजट के ऊपर इतने महत्त्वपूर्ण विषयों को ला देना कहां तक संगत है? मेरी समझ में नहीं आता कि उसका जवाब क्या दूं। उनके भाषण का तीन चौथाई ऐसे विषयों से संबंध रखता है जो इस हाउस के कम्पिटेन्स के बाहर की चीज है। इसलिये इस तरह की स्पीच से यहां कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। जब मैं कॉलेज का छात्र था तो प्रोफेसरों के लेक्चर सुना करता था। आज इतने दिनों के बाद वैसा लेक्चर सुनने का मौका मिला है। लेकिन इस लेक्चर में कोई ऐसी चीज मैं नहीं पाता हूं जिसको अपनी नजर के सामने रख कर देखूं जिसे इस छोटे से बजट में कुछ मदद मिल सके। आज हमारी सबसे जरूरी चीज क्या है। हमारे भवन के बहुत से सदस्यों ने कुछ जरूरी चीजों की तरफ इशारा किया है। लेकिन इस बात को नहीं कहा है कि उन्हें हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल उनके ध्यान में रहता तो हम इस नतीजे पर पहुंचते और हमें उन जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती। लेकिन उन्होंने न अपनी मदद की न हमारी मदद की। हम सब लोग इस सभा के सदस्य हैं और सब लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां आये हैं सब लोग जनता की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, तो यह रास्ता ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख कर अगर बजट को पढ़ते और बजट की कमी को पूरा करने के लिये अगर कोई रास्ता निकाल सकते तो मुझे खुशी होती। इस उद्देश्य से शायद ही किसी को कोई मतभेद होगा। मैं नहीं जानता

ओपेन बोरिंग के लिए सबसिडी ।

A*११२। श्री नन्दकिशोर नारायण—क्या माननीय मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा ओपेन बोरिंग कराने में जो सबसिडी दिया जाता था वह बन्द कर दिया गया है और इनटेन्सिभ ब्लौक में भी २५ प्रतिशत ही ओपेन बोरिंग के लिए सबसिडी दिया जाता है जब कि पोखरा, बांध आदि में शत प्रतिशत मदद किया जा रहा है ।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह—इसका भी उत्तर वही है जो प्रश्न संख्या १११ के उत्तर में दिया गया है ।

जोरीआही ग्रामवासियों द्वारा कुंए का आवेदन-पत्र ।

*१५१। श्रीमती रामदुलारी सिंह—क्या माननीय मंत्री, जन-स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत वैरगनियां थाने में जोरीआही ग्राम निवासियों ने अपने ग्राम के कुंए की मरम्मती के लिए दर्खास्त दी थी ;

(ख) क्या इस दर्खास्त की प्रतिलिपि शीघ्र कार्य सम्पादन कराने के लिये माननीय मंत्री को मिली थी ;

(ग) अगर खंड (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो यह दर्खास्त किस तारीख को दी गयी और अबतक इस कार्य में कहां तक प्रगति हुई है और उसे पूरा करने में क्या विलम्ब है ?

माननीय श्री देवशरण सिंह—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ग) दर्खास्त २६ फरवरी १९५२ को दी गई थी । उसकी प्रतिलिपि सरकार को ३१ मार्च १९५२ को मिली थी । ग्रामीण क्षेत्रों में नल वितरण करने का तथा कुंआ आदि बनाने का और मरम्मत करने का काम जिला बोर्ड का है । मुजफ्फरपुर जिला बोर्ड को उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया गया है ।

STIPENDS TO HARIJANS OF DHANBAD.

*153. **Shri PURUSHOTTAM CHOUHAN**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Harijan Welfare Department be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that there is a District Harijan Welfare Officer at Dhanbad, but there is no separate District Harijan Stipends Awards Committee for Dhanbad ;

(*b*) whether it is a fact that the earmarked 33% of stipends are never given to Dhanbad by the present Harijar Stipends Awards Committee of Purulia ;

(*c*) if the answers to clauses (*a*) and (*b*) be in the affirmative, will Government consider the advisability of constituting a separate District Harijan Stipends Awards Committee for Dhanbad ?

The **Hon'ble Shri BHOLA PASWAN**: (*a*) Previously there were separate District Harijan Welfare Officers for Dhanbad and Purulia, but for the time being the District Harijan Welfare Officer at Dhanbad looks after the Harijan Welfare work for the whole district of

---

A Transferred.

Manbhum. There is no separate Stipend Award Committee for Dhanbad. The Stipends Committee at Purulia awards stipends to the Harijan students of the whole district of Manbhum.

(*b*) No separate percentage of stipends has been allocated for Dhanbad and Stipends are awarded by the District Harijan Stipends Committee at Purulia to the deserving Harijan stundents reading in schools in the district of Manbhum including Dhanbad. During this year 1952-53, 58 Harijan students of Dhanbad have been awarded stipends out of total number of 166 stipends awarded in the district of Manbhum.

(*c*) The question to constitute a separate Stipends Award Committee according to the recommendation of District Inspector of Schools, Manbhum for Dhanbad is under the consideration of Government.

SUPERSESSION OF DINAPUR NIZAMAT MUNICIPALITY.

*154. **Shri RAM LAKHAN SINGH YADAVA** : Will the Hon'ble Minister, Local Self-Government Department, be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the D. P. I., Bihar, Collector, Patna and the Commissioner, Patna Division, have recommended to the Government for the supersession of the Dinapur Nizamat Municipality;

(*b*) whether it is a fact that the Primary teachers working under the said Municipality have not received their salaries for the last sixteen months or so;

(*c*) if the answer to (*b*) is in the affirmative, the reasons thereof?

The Hon'ble Shri BHOLA PASWAN : (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) The answer is in the affirmative.

(*c*) Due to the financial position of the Municipality being in a very bad condition and due to the slackness on the part of the Executives the Municipality has been running in debit balance for the last several months. Government have several times asked the Municipality to pay off its teaching staff but in the circumstances stated above the Municipality could not do so. Government have asked this Municipality to show cause as to why it should not be superseded.

Shri PRABHUNATH SINGH : I want to know whether any enquiry was made by Government whether the Municipality was able to meet the expenditure or not?

The Hon'ble Shri BHOLA PASWAN :

माननीय सदस्य अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिये एक स्वतंत्र सवाल पूछें।

श्री जगतनारायण लाल। क्या म्युनिसिपलिटी के पास फन्ड नहीं रहने के कारण टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली है?

माननीय श्री भोला पासवान। हां पैसा कम है।